युनाइटेड किंगडम के चैस्टर ज़ू में दुर्लभ प्रजाति की हमबोल्ट पैंनग्विन के नौ चूज़ों का जन्म हुआ है। यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर है। अण्डे से निकलने के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों तक माता-पिता की देखभाल में चूज़े अपने घोंसले में ही रहे। ज़ू में पैंनग्विन व पैरट्स की कीपर सोफी बिस्सेकर ने कहा, ''पैंनग्विन के घोंसलों से आती हल्की-हल्की चहचहाट सुनने और माता-पिता से चिपकी छोटी-छोटी मुलायम गेंदों को देखने से बेहतर कुछ भी नहीं। हम भाग्यशाली हैं, ये चहचहाटें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि यहां 9 बच्चों ने जन्म लिया है।'' हमबोल्ट पैंनग्विन के चूज़े जब अण्डों से निकलते हैं तब उनका वजन 80 ग्राम तक होता है और पहले हफ्ते में ही इनका आकार तीन गुना हो जाता है। वयस्क पैंनग्विन 26-28 इंच लम्बे और 10 पाउण्ड तक वजन के होते हैं। जन्म के बाद शुरुआती तीन माह तक माता- पिता ही बच्चों की देखभाल करते हैं। माता पिता मछली को निगलते हैं फिर उसे हाई प्रोटीन वाले लिक्विड में बदलकर उगल देते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। स्टाफ ने बताया कि, नए चूज़े अपने माता- पिता की निगरानी में तैरना सीख रहे हैं। बिस्सेकर ने कहा, पैंनग्विन के चूज़ों ने घोंसले से बाहर निकल कर अपने माता- पिता से तालाब में तैरने का सबक लेना शुरु कर दिया है, इसके साथ ही वो मछली पकड़ना भी सीखेंगे। कुछ ही हफ्तों में उनके सलेटी पंख हटने लगेंगे और काले-सफेद पंख दिखाई देंगे। ये पंख वॉटर प्रूफ होते हैं। ज़ू कीपर्स ने चूज़ों का नाम फलों के आधार पर रखा गया है। सबसे पहले बाहर आने वाले चूज़े का नाम प्लम, इसके बाद वालों के नाम क्रमशः सटसुमा, लैमन, पपाया, आयोना बैरी, पीच, चैरी, रूबार्ब और बनाना रखा गया है। हमबोल्ट पैंनग्विन इन्टरनैशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर (आई.यू.सी.एन.) की रैड लिस्ट में ''वल्नरेबल'' वर्ग में हैं। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक आवास में इनके विलुप्त होने का भारी खतरा है और ये ''एन्डेन्जर्ड'' वर्ग में आने से मात्र एक कदम ही दूर हैं। आई.यू.सी.एन. के अनुसार विश्व में हमबोल्ट पैंनग्विन की आबादी में केवल 23,800 वयस्क हैं। पैंनग्विन की यह प्रजाति मूलतः चिली और पेरू के तटवर्ती भागों में मिलती है। इनके आवास के साथ बहने वाली ठंडी हमबोल्ट धारा में प्रचुर मात्रा में मछलियां, प्लैंकटन और क्रिल होते हैं जो इनका भोजन हैं। पैंनग्विन की इस प्रजाति व इस ठंडी धारा को ''हमबोल्ट'' नाम 18वीं सदी के खोजी यात्री एलैक्ज़ैण्डर वॉन हमबोल्ट के नाम पर मिला है।

चीन में बैंकों के बाहर सेना के टैंक तैनात किये गये

लोग अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए बैंकों के बाहर विरोध कर रहे हैं तथा बैंकों ने आर्थिक तंगी के कारण फिलहाल पैसा देने से मना कर दिया है

- चीन ने 33 साल पहले भी विरोध की आवाज दबाने के लिए कुछ ऐसा ही किया था, तब सेना को लोगों के ऊपर टैंक चढ़ाने के आदेश दे दिये गये थे।
- चीन के हेनान प्रांत में एक बैंक ने कहा है कि, लोगों की जमा पूंजी को एक निवेश माना जायेगा और कुछ समय बाद ही उनका पैसा वापस लौटाया जायेगा।
- चीन के बैंकों को प्रॉपर्टी सैक्टर में मंदी के कारण भारी नुकसान हुआ है। यहां के आम लोगों की भी 70 प्रतिशत पूंजी रिएलिटी सैक्टर में लगी हुई है।

बीजिंग, 22 जुलाई। चीन में बैंकों के आगे सेना के वॉर टैंक्स खड़े कर दिये गये हैं, दरअसल चीन के बैंकों में पैसा खत्म हो गया है या यूं कहें की बैंक रिजर्व एवं करंसी के संकट से गुजर रहे हैं। इस बीच बैंकों ने यह घोषणा की है कि, वे अपने निवेशकों और एवं अन्य प्रकार के पैसे जमा कराने वाले लोगों को फिलहाल उनका पैसा नहीं देंगे।

बैंकों की ओर से हुई इस घटना के विरोध में आम लोग एवं इन्वैस्टर्स सड़कों पर उतर आये हैं तथा खुलकर अपना विरोध जता रहे हैं लेकिन सरकार ने आम जनता के विरोध को दबाने का तानाशाही पूर्ण तरीका निकाला है। यहां बैंकों के बाहर सेना के टैंक खड़े कर दिये गये हैं।

चीन में हुई इस ताजा घटना ने 33 साल पुरानी तस्वीर एक बार फिर जिंदा कर दी है, चीन ने 33 साल पहले तियानमेन स्क्वायर कुछ ऐसा ही किया था, वो घटना अब भी लोगों के जहन में तरोताजा है। अब उसी घटना के जैसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहे हैं। जिनमें सड़कों पर टैंकों को खड़े हुए देखा जा सकता है। मामला ये है कि चीन के एक बैंक ने ऐसी घोषणा की है, जिसने निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। जिन लोगों का पैसा इस बैंक में जमा है, वो बैंक के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। इन्हीं लोगों को बाहर रोकने के लिए टैंक तैनात किए गए हैं। चीन के हेनान प्रांत में टैंकों की एक लंबी कतार देखी गई है और इसके पीछे का कारण बैंक का एक फैसला है।

चीन के बैंक की हेनान ब्रांच की तरफ से लोगों से कहा गया है कि उन्होंने जो भी रकम बैंक में जमा की है, वह अब एक निवेश माना जाएगा और उस पैसे को निकाला नहीं जा सकता है। यही वजह है कि बैंक के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और बैंक के बाहर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी एकत्रित हो रहे हैं। बैंक ने अपने यहां जमा सारे पैसे को फ्रीज कर दिया है और अब जमाकर्ता अपना पैसा जारी करने की मांग कर रहे हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके अनुसार, चीन की पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) यानी चीनी सेना ने सड़कों पर टैंक तैनात करने का काम किया है। इसका मकसद है, बैंक की रक्षा करना।

मीडिया के अनुसार, हेनान प्रांत में स्थित इस बैंक की तरफ से जब से कहा गया है कि लोग यहां जमा अपने पैसे को नहीं निकाल सकते हैं, तभी से हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना को 4 जून, 1989 में तियानमेन स्क्वायर पर हुई घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जिसमें चीन सरकार ने सेना को आदेश दिया था कि वह लोगों पर टैंक चढ़ा दे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ठीक इसी समय चीन में इस घटना से जुड़े शब्दों को सेंसर कर दिया गया था। चीन के हेनान में स्थित बैंक ने लोगों से वादा किया था कि उनका पैसा 15 जुलाई तक लौटा दिया जाएगा। लेकिन कुछ ही लोगों को उनका पैसा वापस मिला है और बाकी के लोग अब भी इंतजार ही कर रहे हैं।

चीन के 31 में से 24 प्रांतों के लोग चीन के राष्ट्रपति शी जिपिंग की नीतियों से परेशान होकर विद्रोह पर उतर आए हैं। इन प्रांतों में 235 हाउसिंग प्रोजेक्ट के 1.3 करोड़ लोग होम लोन की किस्त जमा नहीं करा रहे हैं।

दरअसल, कोरोना काल के दौरान चीन में लॉकडाउन और सख्त कोविड नीतियों के चलते प्रॉपर्टी सेक्टर को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं पा रहे हैं।

गौहर चिश्ती 7 दिन की रिमाण्ड अवधि के बाद अदालत में पेश, भेजा जेल

पुलिस ने बताया कि अजमेर जिला पुलिस को रिमाण्ड अवधि के दौरान पूछताछ में गौहर चिश्ती के अजमेर से बाहर, देश से बाहर तथा पी.एफ.आई. से किसी तरह के लिंक होने के सबूत नहीं मिले हैं

- चिश्ती ने गत 17 जून को मुस्लिम समुदाय की रैली में जो भड़काऊ बयान दिए और नारेबाजी की, वह उसने देश के माहौल से भावावेश में आकर की। पुलिस को गौहर चिश्ती के उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल साहू हत्या प्रकरण में हाथ होने अथवा हत्या के आरोपित रियाज अत्तारी एवं गौस मोहम्मद से किसी तरह का संपर्क होने के प्रमाण नहीं मिले हैं। उदयपुर कांड में हत्यारों ने वही नारे लगाए, जो उसने लगाए थे, इसलिए वह घबरा कर अजमेर से फरार हो गया था।

अजमेर, 22 जुलाई (कास)। सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के बाहर खड़े होकर भड़काऊ बयान देने व नारेबाजी करने के आरोप में गत सात दिन से पुलिस रिमाण्ड पर चल रहे खादिम गौहर चिश्ती को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में हाई सिक्योरिटी जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि अजमेर जिला पुलिस को रिमाण्ड अवधि के दौरान पूछताछ में गौहर चिश्ती के अजमेर से बाहर, देश से बाहर तथा पीएफआई से किसी तरह के लिंक होने के सबूत नहीं मिले हैं। यह जानकारी दी अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने।

सांगवान शुक्रवार को सुबह अजमेर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पुलिस को गौहर चिश्ती के बैंक खातों से भी किसी तरह का संदिग्ध ट्रांजिक्शन होने की जानकारी नहीं मिली है। गौहर चिश्ती ने गत 17 जून को मुस्लिम समुदाय की रैली में जो भड़काऊ बयान दिए और नारेबाजी की वह उसने देश के माहौल से भावावेश में आकर की। पुलिस को गौहर चिश्ती के उदयपुर के टेलर कन्हैया लाल साहू हत्या प्रकरण में हाथ होने अथवा हत्या के आरोपित रियाज अत्तारी एवं गौस मोहम्मद से किसी तरह का सम्पर्क होने के प्रमाण नहीं मिले हैं।

उदयपुर काण्ड में हत्यारों ने वही नारे लगाए, जो उसने लगाए थे, इसलिए वह घबरा कर अजमेर से फरार हो गया था। पुलिस ने पूछताछ के दौरान उससे सब जानकारी की तस्दीक की कि उसकी किसने मदद की एवं वह किस तरह अजमेर से हैदराबाद तक फरार हुआ। इस मामले में पुलिस ने पूर्व में चार आरोपियों को भी पकड़ा था। इसके अलावा गौहर की मदद करने व फरारी में पनाह देने के आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया जिन्हें अदालत से जमानत मिल गई है। पुलिस से किसी अन्य खुफिया एजेंसी ने अभी तक कोई सम्पर्क नहीं किया है। पुलिस का अनुसंधान आरोपित के न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुए भी जारी रहेगा।

श्रीलंका के नये प्रधानमंत्री बने दिनेश गुणवर्धने

- दिनेश गुणवर्धने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी फिलिप गुणवर्धने के बेटे हैं।

कोलंबो, 22 जुलाई। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के सहपाठी और पूर्व पब्लिक ऐडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने अब प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जल्द ही राष्ट्रपति विक्रमसिंघे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिला सकते हैं। शुक्रवार को विक्रमसिंघे नए मंत्रिमंडल का भी ऐलान कर सकते हैं। गौरतलब है कि, श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन के बाद पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद संसद में हुए चुनाव में विक्रमसिंघे को सबसे ज्यादा वोट मिले और वह राष्ट्रपति चुने गए।

गोटाबाया राजपक्षे ने महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनाया था। गोटाबाया के पलायन के बाद स्पीकर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिथ प्रेमदासा ने कई बार भारत से मदद की गुहार लगाई है।

निर्णायक पड़ाव में पूरी तरह पिछड़ते नज़र आ रहे हैं ऋषि सुनक

कंज़र्वेटिव पार्टी के 730 सदस्यों में से 62 प्रतिशत ने बुधवार और गुरुवार को कहा कि, वे लिज़ ट्रस के पक्ष में मतदान करेंगे

- 'खलीज टाइम्स' की शुक्रवार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी कि, लिज़ ट्रस ने ऋषि सुनक पर 28 अंकों की बढ़त हासिल कर ली है।
- केवल 38 प्रतिशत सांसदों ने ऋषि सुनक को समर्थन देने की घोषणा की है।

लंदन, 22 जुलाई (वार्ता)। ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री पद की दौड़ को लेकर चुनाव पूर्व किये गये एक सर्वे में विदेश मंत्री लिज ट्रूज भारतीय मूल के पूर्व मंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ मजबूत स्थिति में दिखायी दे रही है। सुश्री ट्रूज ने सुनक पर 28 अंकों की बढ़त हासिल कर ली है।

'खलीज टाइम्स' की शुक्रवार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गयी। इससे पहले गुरुवार को कंज़रवेटिव पार्टी के सदस्यों ने सुनक और सुश्री ट्रूज को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आखिरी स्तर तक पहुंचने के लिए वोट किया। अब इन दोनों में से कोई एक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री होंगा।

सर्वे के मुताबिक कंजरवेटिव पार्टी के 730 सदस्यों में से 62 प्रतिशत ने बुधवार और गुरुवार को कहा कि वह ट्रूज के पक्ष में मतदान करेंगे और 38 प्रतिशत सुनक के साथ नजर आये, इनके अलावा बचे अन्य ने कहा कि वह वोट नहीं देंगे और या फिर अभी कुछ कह नहीं सकते। रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रूज को देश में हर आयु समूह में भी सुनक पर बढ़त मिली है। केवल एक जगह जहां सुनक को ट्रूज पर बढ़त मिल सकती है, वह हैं बचे हुए 2016 वोट।

अंबानी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उक्त जनहित याचिका में अंबानी के सिक्योरिटी कवर को चुनौती दी गई थी। केन्द्र सरकार को अंबानी परिवार को सिक्योरिटी कवर जारी रखने के निर्देश देते हुए बैंच ने हाई कोर्ट के याचिकाकर्ता को सुने जाने के अधिकार पर सवाल उठाया। उसने कहा कि हाई कोर्ट को जनहित याचिका पर सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अंबानी सरकार द्वारा उपलब्ध सिक्टोरिटी कवर की कीमत अदा कर रहे हैं।

मुर्मू को...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा नेतृत्व वाले नैशनल डैमोक्रेटिक एलायंस प्रत्याशी के रूप में गुरुवार को निर्वाचित घोषित किया गया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मतों के भारी अन्तर से हराया। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 5 वर्ष का कार्यकाल सोमवार को समाप्त हो रहा है। वे इस दिन अपने सामान सहित नए आवास 12 जनपथ में शिफ्ट हो जाएंगे जहां वे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पड़ोसी होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी उनके नए आवास तक छोड़ने जाएंगे। नवम्बर 12, जनपथ में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. रामविलास पासवान करीब तीन दशक तक रहे थे।

जोहड़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अवैध रूप से मॉल, कॉलोनी और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की अनुमति दे दी, जबकि अब्दुल रहमान के मामले में हाईकोर्ट तय कर चुका है कि तालाब, जोहड़, नदी-नाले आदि की जमीन पर निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा इकोलॉजिकल क्षेत्र की जमीन पर भी व्यावसायिक व आवासीय निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जोधपुर में बनेगा बार काउन्सिल का नया भवन

- बार काउन्सिल के इस नए भवन के लिए सरकार ने 14.37 करोड़ रूपए मंजूर किए हैं।

जोधपुर, 22 जुलाई (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर स्थित मुख्य पीठ के परिसर में 14.37 करोड़ की लागत से बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान का नया भवन बनेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस भवन का निर्माण राजस्थान राज्य सडक़ विकास एवं निर्माण निगम (आरएसआरडीसी) द्वारा किया जाएगा। बार काउन्सिल के नवीन भवन के भूतल पर 500 व्यक्तियों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, स्ट्रॉन्ग रूम, विद्युत कक्ष व स्टाफ रूम आदि का निर्माण तथा जमीन तल पर बार काउन्सिल के सचिव व पदाधिकारियों के कक्ष व अन्य सुविधाएं तैयार की जाएंगी। इसके प्रथम व द्वितीय तल पर काउन्सिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कक्ष, मीटिंग हॉल, लाइब्रेरी, ड्राइवर डोरमैटरी, मल्टीपरपज हॉल तथा ऑफिस आदि का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष2022-23के बजट में इस संबंध में 8.53 करोड़ के वित्तीय प्रावधान की घोषणा की गई थी। ऑडिटोरियम एवं निर्माण क्षेत्र में बढ़ोतरी होने के कारण सुविधाओं का विस्तार करते हुए मु.मंत्री गहलोत ने 14.37 करोड़ रुपए की संशोधित राशि के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

भगौड़े

नई दिल्ली, 22 जुलाई (वार्ता)। आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)-केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) हजारों करोड़ रुपए लूटकर भागने वाले नीरव मोदी, विजय माल्या, नितिन संदेशरा को नहीं पकड़ पाती है जबकि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार दिखती है, जिन्होंने देश को शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल दिया है।

सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि भारत के इतिहास में भ्रष्टाचार का कीर्तिमान बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) है। जिसके नाम पर एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में कैमरे पर दलाली लेते हुए पकड़ा गया हो, आज वह पार्टी एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे तमाम मनगढ़ंत और फर्जी मामले दिल्ली सरकार के खिलाफ बना रही है।

चीन में ''सब प्राइम''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लेकिन घर खरीदने वालों को मकानों का पजेशन नहीं दिया जा रहा है।

इससे जनता क्रोधित हो गई, जो कि अधिकांशतः उन लोगों की आबादी है जो बीजिंग से लेकर शंघाई या शेंज़न तक फैली हुई है। यद्यपि मकानों के कई खरीदारों ने अपनी बकाया इन्टॉलमैन्ट्स चुका दी है, लेकिन वे बकाया चल रहे भविष्य के मॉर्टगेज पेमैन्ट्स को चुकाने से मना कर रहे हैं।

ये अनुभव प्रसन्नतादायक नहीं रहे हैं। कई होम कन्स्ट्रक्शन कम्पनियां फण्ड्स को लेकर संकट में फंस गई हैं। चीन की ज़ीरो कोविड की नीति के कई परिणाम हुए हैं। वैश्विक महामारी ने नए घरों की मांग में कमी ला दी है। अतः हाउसिंग कम्पनियों की व्यवहार्यता निरन्तर संशयशुक्त होती जा रही है।

दूसरे, विस्तृत क्षेत्रों में बार-बार लगाए गए लॉकडाउन ने उद्योग व कारोबार के प्रदर्शन पर असर डाला है। बड़े व्यापारिक संस्थान तो इस संकट से पार पा गए, लेकिन कई छोटे कारोबारी मुश्किल में है और अपना व्यापार बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। अब मांग में कमी और सप्लाई चेन्स में व्यवधान के कारण बिल्डर्स अपने बैंक ऋण चुकाने से पीछे हट रहे हैं। कन्स्ट्रक्शन कम्पनियां भी बैंकों को कर्ज चुकाने से इंकार कर रही है। बैंक पहले ही जबर्दस्त दबाव में है और अब हाउस बिल्डिंग कम्पनियों द्वारा अपना बकाया ब्याज और मूलधन चुकाने से इंकार किए जाने से कई बैंकों का अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल हो गया है।

इसमें एक मौजूदा समस्या भी शामिल है। वित्तीय क्षेत्र के बहुत सारे लोग पिछले दो वर्षों से तनाव से गुजर रहे हैं। अब क्रेडिटर्स द्वारा अपने पुनर्भुगतान व्यवस्था का सम्मान करने से इंकार करना एक बड़ा आघात सिद्ध हो सकता है। इसके वित्त का पूरा घूमना प्रभावित हो सकता है।

दो सप्ताह पहले, कुछ छोटे बैंक संकट में आ गये हैं। उनके ऋणों की वापसी नहीं हुई थी तथा वे अब चलते रहने की स्थिति में नहीं है। इससे एक डर पैदा हो गया है। लेकिन चीनी अधिकारियों ने इन्हें संकट से बाहर निकालने के लिये कुछ नहीं किया है। यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि छोटे व्यवसाय अपना अस्तित्व कैसे कायम रख पायेंगे।

चुनाव के बाद सपा गठबंधन टूटने का इतिहास हमेशा कायम रहा है

लखनऊ, 22 जुलाई। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर चर्चा में बने हुए हैं। पहले विधानसभा का चुनाव अखिलेश यादव के गठबंधन के साथ लड़ा। उनकी पार्टी से 6 विधायक जीतकर आए। लेकिन गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। विपक्ष में बैठे। उम्मीद की गई कि अखिलेश और राजभर का यह गठबंधन कम से कम आगामी लोकसभा चुनाव 2024 तक तो चलेगा ही। लेकिन इतिहास

- इस बार चर्चा है कि, ओ.पी. राजभर सपा गठबंधन त्याग कर योगी मंत्रिमण्डल जॉइन करने वाले हैं।

दोहराते हुए गठबंधन टूटने की कगार पर है। लेकिन राजभर खुद गठबंधन नहीं तोडना चाहते। वहीं आज सुबह खबर आती है कि ओम प्रकाश राजभर को राज्य सरकार एनडीए श्रेणी की सुरक्षा दे रही है। जिसके बाद चर्चा चल पड़ी कि वे योगी सरकार में एक बार फिर से शामिल हो रहे हैं। इसके पीछे राष्ट्रपति चुनावों में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देना भी एक कारण बताया गया।

'उप राष्ट्रपति पद का चुनाव अहम्,...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इन तीनों नेताओं की मीटिंग के बाद ही, ममता बनर्जी ने अपने भतीजे से कह दिया था कि वे टी.एम.सी. के मतदान से अलग रहने के बारे में एक बयान जारी कर दें। इस बयान से आम लोगों में इस धारणा को मजबूत करने का काम भी किया है कि विपक्षी एकता असम्भव हैं।

विपक्षी नेताओं ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि अल्वा की उम्मीदवारी के बारे में ममता बनर्जी से परामर्श नहीं किया गया था। विपक्षी नेताओं ने कहा कि पहले वे किसी की भी पहुँच से बाहर हो गई थीं तथा दूसरे, उन्होंने विपक्ष की उस मीटिंग में किसी टी.एम.सी. नेता को नहीं भेजा, जिसमें अल्वा की उम्मीदवारी पर चर्चा हुई थी तथा उसे अन्तिम रूप दिया गया था।

एक अन्य नेता ने कहा कि ममता बनर्जी को मार्गरिट अल्वा की उम्मीदवारी के विषय में बता दिया गया था जिन्हें वे उसी समय से जानती हैं, जब ये दोनों कांग्रेस में थीं।

वोटिंग से अलग रहने के निर्णय से, तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष की एकता पर ताजातरीन प्रहार किया हैं। इससे पहले, शिवसेना तथा जे.एम.एम. ने राष्ट्रीपति चुनाव में नैशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (एन.डी.ए.) प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था, जो अब राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुकी हैं। नेशनल कांग्रेस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी नेताओं की एकता की तुलना प्राचीन ग्रीक पात्र ''काइमेरा'' से की है, जिसे अब असम्भव विचार या आशा के अर्थ में लिया जाने लगा हैं। उन्होंने कहा कि अन्ततोगत्वा, राजनैतिक दल करेंगे वही, जो उनके स्वयं के हित में होगा।

उमर अब्दुल्ला ने कल ट्वीट किया, '' विपक्षी एकता एक प्रकार से काइमेरा हैं। अन्त में, पार्टियाँ वही करेंगी, जो उनके हित में होगा और ऐसा होना भी चाहिये। जम्मू-कश्मीर उस दिन का साक्षी है, जब 2019 में हमारे ''मित्र हमें निस्सहाय स्थिति में छोड़ गये थे।.....''

बनर्जी के भतीजे अभिजीत बनर्जी ने कल घोषणा की थी कि उनकी पार्टी ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि धनखड़ तथा अल्वा-दोनों में से किसी को समर्थन ने किया जाये।

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने पत्रकारों को बताया, ''एन.डी.ए. (भाजपा के नेतृत्व वाला नेशनल डेमोक्रटिक अलायंस) के उम्मीदवार के समर्थन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। एक ऐसी पार्टी, जिसके दोनों सदनों में 35 सांसद हैं, के साथ बिना किसी समुचित विचार विमर्श के जिस तरह से विपक्षी उम्मीदवार तय कर लिया गया, (उसके परिणाम स्वरूप) हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि मतदान-प्रक्रिया से अलग रहा जाये।''

धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से, वे बंगाल से दिल्ली चले जायेंगे तथा बनर्जी के लिये, वह एक बड़ी जीत एवं खुशी का दिन होगा। मुख्यमंत्री तथा धनखड़ के बीच पिछले तीन साल निरन्तर टकराव चलता रहा है तथा बनर्जी राज्यपाल पर आरोप लगाती रहीं हैं कि वे केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा के आदेश पर उन्हें परेशान करते रहते हैं।

भारत के राष्ट्रपतियों के खट्टे-मीठे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

14,650 वोटों से जीते थे। के.आर. नारायणन तथा डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जीत विशेष बड़ी जीत के रूप में रहीं। नारायणन की जीत का अन्तर 9,05,659 तथा कलाम की जीत का अन्तर 8,15,518 वोटों का रहा।

जहाँ राष्ट्रपति पद देश का सर्वोच्च संवैधानिक एवं गरिमापूर्ण पद है लेकिन कई राष्ट्रपतियों, जैसे प्रतिभा पाटिल तथा रामनाथ कोविंद के कार्यकाल अधिकाशतः शान्त किस्म के रहे। कुछ राष्ट्रपति उनके साहसिक तथा निर्णायात्मक कदमों के लिए याद किये जायेंगे। उदाहरण के लिये, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की आपत्तियों की अनसुनी करते हुये, गुजरात के पुनर्निमित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिये गये थे। हिन्दू कोड बिल को लेकर भी, नेहरू के साथ उनके काफी मतभेद थे। ज्ञानी ज़ैल सिंह, जो गांधी-नेहरू परिवार के प्रति घोर निष्ठावान माने जाते थे, ने पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल वापस कर दिया था। राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रस्तावित विधेयक से सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह आम व्यक्ति के पत्रों को खोल सके। ज्ञानी ज़ैल सिंह के कार्यकाल के दौरान, राजीव गांधी सरकार को बर्खास्त किये जाने की साजिश के बारे में भी एक विवाद पैदा हो गया था। डॉ. कलाम, जो एन.डी.ए. के प्रत्याशी के रूप में राष्ट्रपति चुने गये थे, ने 2002 के साम्प्रदायिक दंगों के तुरन्त बाद गुजरात जाने का निर्णय लिया था। उनका विचार दंगापीड़ितों के ज़ख्मों पर सहानुभूति का मरहम लगाने का था। कुछ राष्ट्रपतियों, जैसे शंकर दयाल शर्मा, आर. वेंकटरमण तथा के.आर. नारायणन के कार्यालय इस अर्थ में महत्वपूर्ण रहे कि उनके कार्यकालों में देश में राजनैतिक अस्थिरता रही तथा कई गठबंधन सरकारें बनी तथा गिरीं। नारायण ने तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल सरकार के उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने के निर्णय तथा उसके बाद, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के बिहार की राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करने के निर्णय पर ऐतराज जाहिर किया था। हालाँकि वाजपेयी सरकार उस समय बहुमत खो चुकी थी, जब कारगिल युद्ध चरम पर था, लेकिन राष्ट्रपति नारायणन ने सरकार को युद्ध समाप्ति तक बने रहने दिया था।

- इन राष्ट्रपति के कार्यकाल की तुलना में प्रतिभा पाटिल व रामनाथ कोविंद का कार्यकाल साधारण व शांत रहा है।

चारागाह...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नायब तहसीलदार ने अपीलार्थियों के निर्माण को हटाने के आदेश दे दिए। अपील में कहा गया कि अपीलार्थियों के पास और कोई आवास नहीं है। ऐसे में उनके निर्माणों को नहीं तोड़ा जाए और राज्य सरकार को इन्हें नियमित करने के निर्देश जारी किए जाए।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908